Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies
Online ISSN 2278-8808, SJIF 2024 = 8.153
https://www.srjis.com/issues_data/227
Peer Reviewed & Refereed Journal, Jan-Feb 2024, Vol- 12/81
https://doi.org/10.5281/zenodo.10862811

राजस्थान के माध्यमिक विद्यालयों में सूचना, संचार और प्रौद्योगिकी (भरतपुर जनपद के विशेष संदर्भ में)

ध्रुव कुमार एवं डॉ मृत्युंजय मिश्रा
शोध–छात्र संस्कृति विश्व विद्यालय, मथुरा
(शोध निर्देशक) *शिक्षा विभाग संस्कृति विश्व विद्यालय, मथुरा*

Paper Received On: 20 Jan 2024

Peer Reviewed On: 26 Feb 2024

Released On: 01 March 2024

Abstract

*भारत सरकार द्वारा सूचना–संचार एवं प्रौद्योगिकी के शिक्षा क्षेत्र में उपयोगिता वर्द्धन हेतु, मार्च 2009 से RMSA योजना के तहत प्रदान किए गए गुणवत्ता हस्तक्षेप में शिक्षकों की नियुक्ति 30:1 विद्यार्थियों:शिक्षक अनुपात को बनाए रखना, विज्ञान, गणित और अंग्रेजी शिक्षा, विज्ञान प्रयोगशालाओं, **आईसीटी सक्षम शिक्षण**, पाठ्यक्रम और शिक्षण सुधारों पर ध्यान केंद्रित करना है। सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं से, ग्रामीण अंचल की तुलना में नगरीय क्षेत्र के विद्यालय अधिक लाभन्वित हैं। ग्रामीण अंचल में इण्टरनैट की सुविधा का अभाव, तकनीकि शिक्षकों का सरकार द्वारा नियुक्त न किया जाना, शिक्षकों पर अतिरिक्त शिक्षणेत्तर कार्यों का भार एवं सरकारी अधिकारियों द्वारा योजनाओं के संचालन विषयक विरोधभासी आदेश जारी किया जाना इसके प्रमुख कारण है। माध्यमिक स्तरपर संचार एवं प्रौद्योगिकी शिक्षण के क्षेत्र में आशातीत प्रतिफल के लिये तकनीकि शिक्षकों की सरकारी स्तर पर नियुक्ति एवं संसाधनों की उपलब्धता आवश्यक है।*

पारिभाषिक शब्दावली : *ग्रामीण विद्यालय, सूचना–संचार,, प्रौद्योगिकी, ।*

समस्या में प्रयुक्त शब्दों का परिभाषीकरण :

वैज्ञानिक अध्ययन की यह एक प्रमुख आवश्यकता है कि समस्या में प्रयुक्त शब्दों की निश्चित परिभाषा प्रस्तुत की जाये जिससे समस्या की विषयवस्तु, क्षेत्र तथा उद्देश्यों का स्पष्ट ज्ञान हो सके। इस अवधारणा की पूर्ति हेतु समस्या में प्रयुक्त शब्दों की व्याख्या निम्नवत् प्रस्तुत की गई है–

ग्रामीण विद्यालय : ग्रामीण विद्यालय से अभिप्राय उन विद्यालयों से है जो शहर से दूर गांवों में स्थित है।

नगरीय विद्यालय : शहरी विद्यालयों से अभिप्राय उन विद्यालयों से है जो शहर में स्थित हैं।

Copyright © 2024, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

सूचना संचार एवं प्रौद्योगिकीः विद्यालयों में उपलब्ध एवं प्रयुक्त आधुनिक संसाधन जैसे कम्प्यूटर, इण्टरनैट, ई–पुस्तकें एवं ई–संसाधन।

अध्ययन के उद्देश्य : माध्यमिक विद्यालयों में सूचना संचार एव प्रौद्योगिकी संसाधनों की उपलब्धता के विभिन्न पक्षों का वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अध्ययन करना।

अध्ययन के चर : 1. आश्रित चर :सूचना संचार एव प्रौद्योगिकी संसाधन
2. निराश्रित चर : ग्रामीण विद्यालय एवं नगरीय विद्यालय

प्रविधिः प्रस्तुत अध्ययन में विश्लेषणात्मक शोध प्रवधि का प्रयोग किया गया है।

उपकरणः तथ्य संकलन के लिए स्वनिर्मित अनुसूची का प्रयोग किया गया है। प्रस्तुत अध्ययन के लिए माध्यमिक विद्यालयों का चयन किया गया है। प्रतिदर्श के चयन में उद्देश्यपूर्ण निदर्शन को अपनाया गया। सम्पूर्ण प्रतिदर्श में कुल 100 माध्यमिक विद्यालयों (50 ग्रामीण एवं 50 नगरीय) का इकाइयों के रूप का चयन किया गया है।

तथ्य विश्लेषण एवं परिलब्धियाँ :

भरतपुर जिला $27^0 22'$ से $27^0 50'$ उत्तरी अक्षांश व $77^0 48'$ से $78^0 17'$ पूर्वी देशान्तर के मध्य स्थित है जिले के उत्तर में हरियाणा राज्य के रेवाड़ी, नूंह, फरीदाबाद, पूर्व में उत्तरप्रदेश राज्य के मथुरा और आगरा जिले, दक्षिण में धौलपुर जिला एवं मध्यप्रदेश का मुरैना जिला और पश्चिम में करौली जिला, दौसा जिला व अलवर जिला से सीमा लगती है (करौली के हिण्डोन से, दौसा के महुआ से एवं अलवर के कठूमर, रामगढ़, तिजारा से भरतपुर की सीमा लगती है।) जिले की आकृति कटी–फटी तथा विषम है जिले का कुल क्षेत्रफल 5066 वर्ग कि.मी. है। भरतपुर जिले की जलवायु शुष्क है ग्रीष्म ऋतु में बहुत गर्मी, शीत ऋतु में बहुत सर्दी और वर्षा ऋतु में मानसून अल्पकालीन होता है। जिले का औसत तापमान 28 डिग्री सेन्टीग्रेड रहता है। तथा वर्षा का वार्षिक औसत 62.15 सेन्टीमीटर है। भरतपुर जिले की भरतपुर व नदबई तहसील मैदानी व समतल है जबकि बयाना व रूपवास तहसीलों में पहाड़ियाँ हैं।

आर्थिक नियोजन में शिक्षा महत्वपूर्ण घटकों में से एक मानी गयी है और आर्थिक विकास के क्षेत्र में शिक्षा के योगदान को स्वीकार किया गया है। शैक्षिक विकास निरन्तर चिन्तन एवं शोध का विषय रहा है। भारत में ही नहीं बल्कि विकसित देशों में भी 'शैक्षिक विकास' के संकेतकों पर निरन्तर शोध के द्वारा विस्तृत आंकड़ों के संग्रह के द्वारा नियन्त्रण एवं सुधार के प्रयास किये जाते रहे हैं। गाँधी जी ने सुझाया था कि बच्चे को रूपातंरित होते सामाजिक परिदृश्य का एक अंग बनाने के लिए बच्चे के आस–पास के पर्यावरण, जिसमें मातृभाषा एवं कार्य भी आते हैं, को साधन के रूप में उपयोग किया जाए।

यदि अध्यापक एवं शिक्षा संस्थानों का प्रभाव समाज और राष्ट्र की आशाओं, आवश्यकताओं एवं अपेक्षाओं के आधार पर नहीं होगा तो उनकी सार्थकता पर तो प्रश्न चिन्ह लगना स्वाभाविक ही है, साथ ही उस समाज व राष्ट्र की

Copyright © 2024, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

सभी प्रकार के उत्पादन संस्थानों की जड़ें भी दुर्बल हो जायेंगी। किसी भी राष्ट्र के सर्वांगीण विकास में शैक्षिक संस्थानों का विशेष महत्व होता है।

1968 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति और NCERT (राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्) द्वारा 1975 में पाठ्यचर्या रूपरेखा की रचना की गई। 1976 में संविधान में संशोधन किया गया और शिक्षा के उत्तरदायित्व को समवर्ती सूची में लाया गया और पहली बार वर्ष 1986 में शिक्षा पर पूरे देश की एक राष्ट्रीय नीति बनी। 1992 में संशोधित शिक्षा नीति आई जिसमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात कही गई। 11वीं पंचवर्षीय योजना (2007–12) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का शुभारम्भ किया गया, चूंकि प्रारम्भिक शिक्षा को सर्वव्यापी करना एक संवैधानिक कानून बन गया है इसलिए यह आवश्यक है कि इस अभिकल्पना को माध्यमिक शिक्षा के माध्यम से सर्वव्यापी बनाने की आवश्यकता है। अच्छी और गुणवत्तापूर्ण माध्यमिक शिक्षा सुलभ करवाने के उद्देश्य से 11वीं पंचवर्षीय योजना में माध्यमिक स्तर की शिक्षा को सर्वव्यापी तथा गुणवत्ता सुधार हेतु राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (RMSA) नामक एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम शुरू की गई। इस स्कीम का उद्देश्य आवास से उचित दूरी के भीतर माध्यमिक स्कूल उपलब्ध करवा कर 5 वर्ष के भीतर कक्षा में नामांकन अनुपात 75% करने तथा सभी माध्यमिक स्कूलों में निर्धारित मानदण्डों के अनुसार माध्यमिक स्तर की शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, महिला एवं पुरूष सामाजिक, आर्थिक तथा विकलांगता आधारित बाधाओं को दूर करना।

माध्यमिक विद्यालयों में सूचना, संचार और प्रौद्योगिकी :

स्कूलों में सूचना और प्रौद्योगिकी (आईसीटी) योजना दिसम्बर, 2004 में माध्यमिक स्तर के छात्रों को मुख्यतः अपनी आईसीटी (ICT) कौशल क्षमता वृद्धि और कम्प्यूटर सहायक शिक्षण प्रक्रिया के माध्यम से सीखने के अवसर प्रदान करने हेतु किया गया था। यह योजना छात्रों के विभिन्न सामाजिक, आर्थिक डिजिटल डिवाइड और अन्य भौगोलिक अवरोधों को पार करने का सेतु है। योजना राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को चिरस्थायी आधार पर कम्प्यूटर प्रयोगशालाएं स्थापित करने के लिए सहायता प्रदान करती है। इसका केन्द्रीय विद्यालयों और नवोदय विद्यालयों में स्मार्ट स्कूल स्थापित करने का उद्देश्य भी है जो भारत सरकार के प्रौधोगिकी प्रदर्शकों के रूप में काम करने और आईसीटी कौशल को आस–पास के विद्यालयों में प्रसारित करने हेतु गति प्रदान करनी वाली संस्थाएं है।

योजना के घटक –योजना के प्रमुख 4 घटक है –

- प्रथम : माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक, सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों को कम्प्यूटर सहायक शिक्षा प्रदान करने के लिए राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के साथ भागीदारी।
- द्वितीय : स्मार्ट स्कूलों की स्थापना करना।
- तृतीयः शिक्षक संबंधित हस्तक्षेप जैसे – विशिष्ट शिक्षक की नियुक्ति, आईसीटी में सभी शिक्षकों की क्षमता में वृद्धि करना।

Copyright © 2024, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

- चतुर्थ : केन्द्रीय शिक्षा प्रौद्योगिकी संस्थान (सी. आई. ई. टी.), 6 शिक्षा प्रौद्योगिकी संबंधी राज्य संस्थानों (एस. आई. ई. टी.) और 5 प्रादेशिक शिक्षा संस्थानों (आर. आई. ई.) और आउटसोर्सिंग के माध्यम से भी, ई–विषयवस्तु का विकास करने से है।

जनपद भरतपुर के विद्यालयों का संदर्भित विश्लेषणः

भारत सरकार द्वारा सूचना–संचार एवं प्रौद्योगिकी के शिक्षा क्षेत्र में उपयोगिता वर्द्धन हेतु, मार्च 2009 से RMSA योजना के तहत प्रदान किए गए गुणवत्ता हस्तक्षेप में शिक्षकों की नियुक्ति 30:1 विद्यार्थियोंःशिक्षक अनुपात को बनाए रखना, विज्ञान, गणित और अंग्रेजी शिक्षा, विज्ञान प्रयोगशालाओं, **आईसीटी सक्षम शिक्षण**, पाठ्यक्रम और शिक्षण सुधारों पर ध्यान केंद्रित करना है।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (भारत सरकार) एवं ए. आई. सी. टी. ई. के द्वारा माइक्रोसॉफ्ट के सहयोग से ऑनलाइन शिक्षा हेतु 9 जुलाई 2017 को SWAYAM (Study Webs of Active learning for Young Aspiring Minds) पोर्टल प्रक्षेपित किया गया। मानव संसाधन विकास मंत्रालय (भारत सरकार) एवं NCERT के संयुक्त तत्वावधान से ई–लर्निंग के लिए, जुलाई 2018 में DIKSHA - Digital Infrastructure for Knowledge Sharing Application को प्रारम्भ किया गया । माध्यमिक शिक्षा के सुधार हेतु किए जा रहे सरकारी प्रयासों के मूल्यांकन से सम्बन्धित प्राप्त तथ्यों को निम्न तालिका में प्रदर्शित किया गया है।

प्रस्तुत शोध कार्य में राजस्थान के भरतपुर जनपद के 100 माध्यमिक विद्यालयों से स्वनिर्मित अनुसूची के माध्यम से, विद्यालय प्रबन्ध तंत्र एवं प्रधनाचार्य व शिक्षकों से, प्रत्यक्ष पूछ–ताछ द्वारा संकलित तथ्यों को निम्न तालिकाओं में वर्गाकृत कर विश्लेषण किया गया है।

तालिका 1 : माध्यमिक विद्यालयों में सूचना–संचार संसाधनों की उपलब्धता

क्र0	प्रत्युत्तर/ सूचना–संचार संसाधन उपलब्धता	विद्यालय का प्रकार		
		नगरीय	ग्रामीण	योग
1	सूचना–संचार संसाधन उपलब्ध हैं।	39	24	63
2	सूचना–संचार संसाधन उपलब्ध नहीं हैं।	09	22	31
3	उदासीन प्रत्युत्तर	02	04	06
	योग	50	50	100

प्रस्तुत तालिका में प्रदत्त तथ्यों से स्पष्ट है कि 39 नगरीय एवं 24 ग्रामीण माध्यमिक विद्यालयों में आवश्यक सूचना–संचार संसाधन उपलब्ध हैं।09 नगरीय एवं 22 ग्रामीण माध्यमिक विद्यालयों में सूचना–संचार संसाधन या तो उपलब्ध नहीं हैं या सूचना–संचार संसाधनों का अभाव है।02 नगरीय एवं 04 ग्रमीण विद्यालयों से उदासीन प्रत्युत्तर प्राप्त हुए हैं। स्पष्ट है कि ग्रमीण

Copyright © 2024, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

अंचल की तुलना में नगरीय क्षेत्र के विद्यालय अधिक जागरूक एवं तकनीकि प्रयोग में अग्रणी हैं।

ग्राफ – 1

भरतपुर (राज.) के माध्यमिक विद्यालयों में सूचना–संचार संसाधनों की उपलब्धता

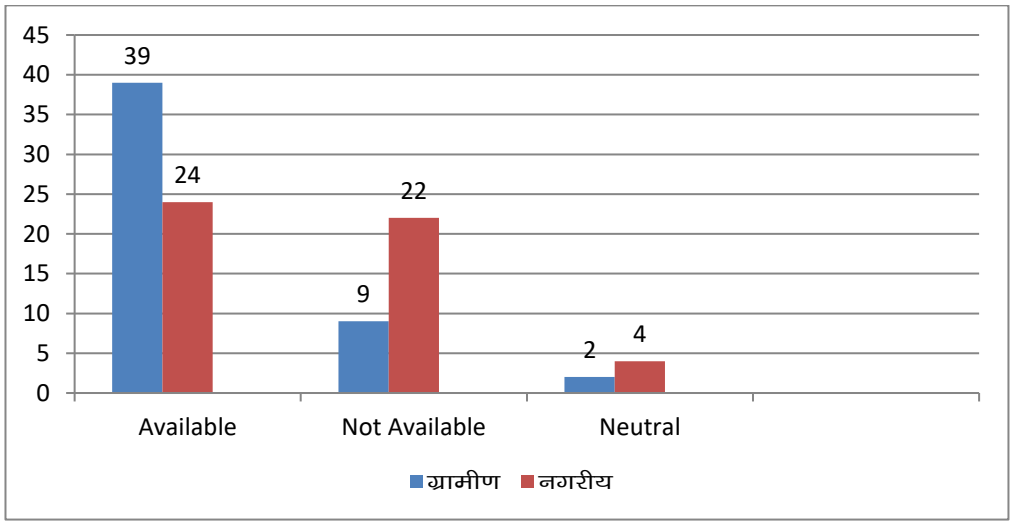

तालिका 2 : विद्यार्थियों एवं शिक्षकों में सरकार द्वारा संचालित ई–लर्निंग संसाधनों एवं एप्लीकेशन्स के उपयोग एवं जागरूकता

क्र0	विद्यार्थियों एवं शिक्षकों में सरकार द्वारा संचालित ई–लर्निंग संसाधनों एवं एप्लीकेशन्स के उपयोग एवं जागरूकता	प्रत्युत्तर आवृत्ति
1.	सरकार द्वारा संचालित विभिन्न ई–लर्निंग संसाधनों एवं एप्लीकेशन्स उपलब्ध हैं एवं उनका प्रयोग किया जा रहा है।	54
2.	सरकार द्वारा संचालित विभिन्न ई–लर्निंग संसाधनों एवं एप्लीकेशन्स उपलब्ध हैं परन्तु उनका प्रयोग नहीं किया जा रहा है।	12
3.	न तो सरकार द्वारा संचालित विभिन्न ई–लर्निंग संसाधन एवं एप्लीकेशन्स उपलब्ध हैं और ना ही उनका प्रयोग किया जा रहा है।	34
	योग	100

प्रस्तुत तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट है कि 54 विद्यालयों में सरकार द्वारा संचालित विभिन्न ई–लर्निंग संसाधनों एवं एप्लीकेशन्स उपलब्ध हैं एवं उनका प्रयोग किया जा रहा है। 12 विद्यालयों में विभिन्न ई–लर्निंग संसाधनों एवं एप्लीकेशन्स उपलब्ध हैं परन्तु उनका प्रयोग नहीं किया जा रहा है। 34 विद्यालयों में न तो सरकार द्वारा संचालित विभिन्न ई–लर्निंग संसाधन एवं एप्लीकेशन्स उपलब्ध हैं और ना ही उनका प्रयोग किया जा रहा है।

Copyright © 2024, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

निष्कर्षः प्रस्तुत प्राथमिक तथ्यों के विश्लेषण से स्पष्ट है कि सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं से, ग्रामीण अंचल की तुलना में नगरीय क्षेत्र के विद्यालय अधिक लाभन्वित हैं। ग्रामीण अंचल में इण्टरनैट की सुविधा का अभाव, तकनीकि शिक्षकों का सरकार द्वारा नियुक्त न किया जाना, शिक्षकों पर अतिरिक्त शिक्षणेत्तर कार्यों का भार एवं सरकारी अधिकारियों द्वारा योजनाओं के संचालन विषयक विरोधभासी आदेश जारी किया जाना इसके प्रमुख कारण है। माध्यमिक स्तरपर संचार एवं प्रौद्योगिकी शिक्षण के क्षेत्र में आशातीत प्रतिफल के लिये तकनीकि शिक्षकों की सरकारी स्तर पर नियुक्ति एवं तत्सम्बन्धित संसाधनों जैसे इण्टरनैट की निर्बाध आपूर्ति एवं वाई–फाई आदि की उपलब्धता आवश्यक है।

REFERENCES:

KUMAR V. 2002 Social Equality. The Constitutional Experiment in
India. New Delhi:S Chand & Company Ltd.
---------- 2005 Encyclopaedia Britannica, p-14
KULHARI G S 2007 Caste Class and Inequality, p-166/67
DUA M. L. 2005 Fifth All India Educational Survey (Vol.1) New Delhi: NCERT.
BHATT, B.D. 1993 Sociology of Education. Kanishka Publishing House, Delhi. p-8
DAWDEKAR S. 1987 Changing Trends In the Education System. The Pioneer,
MAYA S. 1987 Coordinating Education System and Development. Yojana, Nov.1-15, pp.12-18.
MAITRA K 1997 Equality of Educational Opportunity In India. New Delhi: National Publishing House.

Cite Your Article as

Dhruv Kumar & Dr. Mrutunjay Mishra. (2024). RAJASTHAN MAIN MADHYAMIK VIDYALAYO MAIN SUCHANA, SANCHAR AUR PRDAUGIKA (BHARATPUR JANPAD : KE VISHESH SANDHARBH MAIN). In Scholarly Research Journal for Interdisciplinary studies (Vol. 12, Number 81, pp. 238–243). Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.10862811

Copyright © 2024, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies